Formula for Power Allocation to Rajasthan

895. SHRI ONKAR SINGH LAKHAWAT: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether the Rajasthan Government has requested the Central Government to review the formula for allocation of power from the Central power stations, based on projected shortage of power; and

(b) if so, by when Government are likely to review the prevailing formula for allocation of power from Central Sector power stations to ensure additional power to the State which is facing power shortage?

THE MINISTER OF POWER, MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI P. R. KUMARAMANGALAM): (a) and (b) Yes, Sir. The formula for sharing of power from central sector thermal power stations and nuclear power stations was evolved in 1978 and the same is being generally followed. The formula of sharing of power from central sector hydro electric power stations was evolved in 1981 and modified in 1990 and the formula revised in 1990 is being followed. The formula of allocation of power from central sector power stations is working satisfactorily and there is no proposal to revise the same at present.

टिहरी बांध के लक्ष्यों तक पहुंचने में कम्पनियों का विफल रहना

896. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने टिहरी बांध को हर हालत में सन् 2002 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है;

(ख) यदि हां, तो मुख्य बांध और पावर हाउस के संबंध में वर्ष 1998-99 के लिए क्या लक्ष्य रखे गए थे और क्या निर्माण कार्य करने वाली कम्पनियों ने इन लक्ष्यों को प्राप्त किया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इसके लिए उक्त कम्पनियों को दोषी पाया गया है, यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम्): (क) जी, हां। टिहरी जल विद्युत परियोजना चरण-I (1000 मे०वा०) को वर्ष 2002 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

(2) वर्ष 1998-99 (जनवरी, 1999 तक) के दौरान परियोजना के मुख्य बांध और विद्युत गृह के निर्माण के लिए निर्धारित लक्ष्यों को निर्माण कंपनियों द्वारा प्राप्त कर लिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

नई टिहरी में प्लाटों का आवंटन

897. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या विद्युत मंत्री 8 दिसम्बर, 1998 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 131 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टिहरी शहर के डूब क्षेत्र में आने वाले सभी 2438 पात्र परिवारों को नई टिहरी में प्लाट आवंटित कर दिए गए हैं, यदि नहीं तो कितने परिवार शेष रह गए हैं और उन्हें कब तक प्लाट आवंटित कर दिए जाएंगे;

(ख) छाम, जो सड़क पर बसा हुआ एक बाजार है, जैसे उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या मानक तय किए गए हैं जो पूरी तरह डूब क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं;

(ग) इन लोगों को पुनर्वास की सुविधाएं कब तक और कहां प्रदान की जाएंगी; और

(घ) ऐसे डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामीण परिवारों की कुल संख्या कितनी है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम्): (क) पत्र 2438 शहरी आवासीय भूमिस्वामियों में से 2400 आवासीय भूखण्ड का आवंटन किया जा चुका है। बचे हुए भूखण्ड को विकसित किया गया है और वे आवंटन हेतु तैयार हैं।

(ख) ग्राम चाम आंशिक रूप से जलमग्न क्षेत्र में आता है और सड़क के साथ लगी कुछ दुकाने जल मग्नता के अर्न्तगत आ सकती है। मौजूदा पुनर्वास पैकेज के अनुसार भूमि और मौजूदा ढांचों के लिए मुआवजे की राशि देय है। हनुमंत राव समिति की सिफारिशों के आधार पर आंशिक रूप से जलमग्न क्षेत्रों के ग्राम दुकान मालिकों को रिंग रोड के निकट लागत पर दुकान भूखण्ड दिया जाएगा। टिहरी जल विद्युत विकास निगम को तदनुसार कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

(ग) ग्राम क्षेत्र में सभी प्रभावित भू-स्वामियों का पुनर्वास 2002 तक भूमि जब्त किए जाने से पूर्व देहरादून और हरिद्वार जिले में किए जाने की संभावना है।

(घ) जलमग्नता के कारणवश 4909 ग्रामीण परिवार पूर्णत प्रभावित हुए हैं। इसके अतिरिक्त 3998 परिवार आंशिक रूप से प्रभावित हैं जिन्हें पुनर्वासित नहीं किया जाना है। तथापि इन परिवारों को जलमग्नता के अंतर्गत आने वाली भूमि के लिए रोकड़ मुआवजा दिया जाना है।

Availability and Demand of Power

898. SHRI NARESH YADAV: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) what was the overall availability and demand of power State-wise, during 1997-98 and 1998-99 and as on date;

(b) whether there was a shortfall of more than 20 per cent in demand during the same period which is expected to go up in the coming years;

(c) whether there was any proposal under Government's consideration for power production in the public sector to meet this shortage;

(d) if so, whether any decision has been taken in this regard; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF POWER, MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI P. R. KUMARAMANGALAM): (a) and (b) The details of energy requirement, availability and shortage in various States during 1997-98 and 1998-99 (April 1998 to Jan. 1999) are given at the Annexure. [*see Appendix 186, Annexue No. 19*]

(c) to (e) Power is being generated by Central public sector undertakings as well as state utilities and in the private sector. Decision on setting up new projects in the central sector and state sector are taken from time to time in keeping with the annual plan proposals.

बिजली की खपत का आकलन

899. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि, औद्योगिक, वाणिज्यिक क्षेत्रों में तथा घरेलू उपयोग और सरकारी संस्थाओं में बिजली की होने वाली खपत का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो कुल वार्षिक विद्युत खपत में इन क्षेत्रों का प्रतिशत कितना रहेगा और इन क्षेत्रों से आने वाली मांग के संबंध में आकलन किया है; और;

(ग) आगामी दशक में बढ़ने वाली मांग को पूरा करने के लिए सरकार की कार्य-योजना क्या है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम): (क) जी, हां। 15वें विद्युत शक्ति सर्वेक्षण रिपोर्ट में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा घरेलू क्षेत्रों में सम्भावित खपत का आकंलन किया गया है।

(ख) विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की मांग और कुल खपत में विद्युत खपत का प्रतिशत, जैसा कि 15वें विद्युत शक्ति सर्वेक्षण रिपोर्ट में अनुमानित किया गया है नीचे दिया गया है।